भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 328
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

एआई का प्रभाव

328. श्री मनीश तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत के श्रम बाजार पर एआई और स्वचालन के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा एआई और स्वचालन के आने के पश्चात् कार्यबल को अनुकूलित करने हेतु नई नौकरियों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'भारतीय श्रम बाजार को कौशलयुक्त और पुनः कुशल बनाने के लिए कोई परियोजना शुरू की है; और

(घ) क्या सरकार ने मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के "जेनरेटिव एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क इन अमेरिका" शीर्षक वाले अध्ययन का संज्ञान लिया है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि स्वचालन की आवश्यकता वाले कुछ कार्यों जैसे आंकड़ा संग्रह और दोहराए जाने वाले कार्यों वाली नौकरियां एआई द्वारा प्रतिस्थापित हो जायेंगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार था:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) का आयोजन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन करना है। ये चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस के चौथे चरण (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार इन चयनित नौ क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार 3.18 करोड़ था, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था।

क्यूईएस के चौथे चरण (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में अनुमानित रोजगार, क्यूईएस के पहले चरण(अप्रैल-जून, 2021) के दौरान 20.71 लाख की तुलना में बढ़कर 38.31 लाख हो गया है जो आईटी/बीपीओ क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि का संकेत देता है।

सरकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार के विकास के लिए गतिशील प्रवर्तक मानती है। सरकार ने एआई इकोसिस्टम का विस्तार करने और एआई अवसरों को देश के युवाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने, 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति की रीस्किलिंग/अप-स्किलिंग के उद्देश्य से 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' की शुरुआत की है। इनमें एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, बिग डेटा और एनालिटिक्स, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3डी प्रिंटिंग और वेब 3.0 शामिल हैं।

विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना का उद्देश्य, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा आईटी/आईटी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाना है।

सरकार ने दिनांक 30 जुलाई, 2022 को रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम को अखिल स्तर पर सरकारी विद्यालयों के छात्रों तक पहुंचने और उन्हें समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'युवाई: एआई के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों को एआई तकनीक और सामाजिक कौशल के साथ समावेशी तरीके से सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम युवाओं को 8 विषयगत क्षेत्रों- कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी तथा विधि और न्याय में एआई कौशल सीखने और इसे लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पहल की भूमिका तथा महत्व को पहचानती है जिसमें सभी स्तरों पर छात्रों में इस प्रकार के कौशल विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे समसामयिक विषयों की शुरूआत भी शामिल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2019 में अपने संबद्ध स्कूलों में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' की शुरुआत की थी।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

नीति आयोग ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति' (एनएसएआई) जारी की थी। नीति आयोग ने उन पांच क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, जिन्हें सामाजिक जरूरतों को हल करने में एआई से सबसे अधिक लाभ मिलने की कल्पना की गई है: क) स्वास्थ्य देखभाल: गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि, ख) कृषि: किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और बर्बादी में कमी, ग) शिक्षा: शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, घ) स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा: बढ़ती शहरी आबादी के लिए कुशलता और कनेक्टिविटी, और ड) स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन: परिवहन के स्मार्ट और सुरक्षित तरीके तथा बेहतर यातायात और भीड़ की समस्याएं।

*****